आकाशवाणी शिमला

26.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18.00बजे

अनुदान

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत असंबद्ध अनुदानों की पहली किस्त के रूप में 67 करोड़ 95 लाख रुपये जारी किए है। इस धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों में स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति ,घरेलू कचरे का प्रबंधन व उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण कार्य किये जायेगे।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बैंकों से आपदा प्रभावितों को ऋणों की किश्त देने में राहत देने का आग्रह किया है। आज शिमला में हुई राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है ऐसे में लोगों के कर्ज वापिस करने की क्षमता प्रभावित हुई है। बैठक में बैंकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने मुख्य कार्यालयों को इस संबंध में आग्रह करेंगे। मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि ऋणों की अदायगी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो एक सप्ताह के भीतर इस विषय पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट देगी।

जीएसटी सुधार – स्टेशनरी वस्तुएँ

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं, जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो चुके हैं। नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत की पूर्व की चार–स्तरीय संरचना को सरल बनाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो–स्तरीय संरचना बना दी है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर घटने से नागरिकों को काफी राहत मिली है।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 सितम्बर को आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू–ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा।

टीबी जांच

नगर निगम सोलन शहर के सभी वार्डों में टीबी जांच शिविर लगाएगा और शहर के सभी लोगों की इस अभियान के तहत जांच की जाएगी। ये निर्णय नगर निगम सोलन की आज हुई बैठक में लिया गया। निगम आयुक्त एकता कपटा ने कहा कि सभी पार्षद अपने–अपने वार्डों में लोगों को टीबी के बारे में जागरूक भी करेंगे।

राजस्व मामले

प्रदेश सरकार ने राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से अक्तूबर 2023 से अगस्त 2025 तक 4 लाख 33 हजार 2 सौ 42 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया है।

————————————